

Fax. : 011 – 25596515  
E-Mail: nehm1983@gmail.Com  
Web Site - http://www.indiaelectrotherapy.org  
P. B. No. : 9611, Janak Puri, N. D. – 58



25525501  
25525528  
Tel :- (011) 25551774  
25555238  
65631234  
GRAM: "NEHAM"  
Mob: 9210647054

# N.E.H.M. OF INDIA

Authorised by:-

**Ministry of Health & F.W., Govt. of India**

For Promotion, Development & Research

H.O.:-C2C/123, Pocket-12, Janak Puri, New Delhi- 110058 (INDIA)

Ref. No: N/Admn./12

Dt. 16-08-2012

समस्त इलेक्ट्रोपैथी चिकित्सक व छात्रगण

भारत में इलेक्ट्रोपैथी पद्धति की बर्तमान स्थिति क्या है।

महोदय,

समपूर्ण भारतवर्ष में **82** इलेक्ट्रोपैथी चिकित्सा पद्धति की संस्थाएँ/Council/Board/Association चल रहे थे। 5 मई 2010 को स्वास्थ्य मंत्रालय, भारत सरकार ने एक Policy Decision / Notification जारी किया, जिसके तहत/अनुसार **81** संस्थाएँ/Board खत्म/भंग हो गए, अतः भारत में एकमात्र संस्था NEHM के इलेक्ट्रोपैथी चिकित्सक Practice करेंगे, और मेडिकल संस्थान चलेंगे।

भारत सरकार के वरिष्ठ वकील का मत है, कि यदि किसी पद्धति जो मान्यता प्राप्त नहीं है, या कानून के दायरे में नहीं है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप 200 रूपयें में संस्था को पंजीकृत कराकर, आप Degree / Diploma को बांटने लगे/बेचने लगे। यदि कानून/एक्ट/Law नहीं है, तो आप न्यायालय के पास जाकर कहे, कि इस पद्धति का अभी तक कोई कानून/एक्ट नहीं बना है, कृपया डिग्री/डिप्लोमा देने का अधिकार मुझे दे। उस वक्त माननीय न्यायालय उस संस्था की संपूर्ण क्रिया विधि को देखेगी, कि संस्था कौन से/कितने सालों का Course चला रही है, कितने Subject और Syllabus क्या हैं, College खोलने का Term & Condition क्या है इत्यादि, माननीय न्यायालय गौर करेगी, और अपना फैसला सुनाएगी।

**81** रद्द इलेक्ट्रोपैथी संस्थाओं ने, ऐसा कुछ नहीं किया। भारत वर्ष में एकमात्र संस्था NEHM of India ने माननीय हाईकोर्ट दिल्ली एवं सुप्रीम कोर्ट से अधिकार डिप्लोमा/प्रमाण पत्र एवं प्रेक्टिस रजिस्ट्रेशन हेतु अधिकार प्राप्त किए थे।

Electrotherapy/ Electro Homoeopathy is Governed by Ministry of Health & F.W.,  
Govt. of India vide order / RTI V.2501/130/2012-HR.

18 वर्षों से (31904/91,Pending) माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में NEHM Electropathy पद्धति की सरकारी मान्यता की लड़ाई लड़ रहा था। वर्ष 2009 में याचिका माननीय जजों के सामने रखी गई। NEHM के वकील ने न्यायालय से कहा कि 18 वर्षों में NEHM ने काफी कुछ न्यायालय के आदेश जो पक्ष (Favour) में है। भारत सरकार के वकील ने इसका विरोध किया। न्यायालय इलाहाबाद ने NEHM को 7 दिन का समय Supplementary Affidavit दाखिल करने के लिए कहा। NEHM ने University द्वारा प्राप्त औषधियों की रिपोर्ट (Blue Electropathy) का 84%, Liver की Cure करना, Kidney से Stone निकाल देना, इत्यादि रिपोर्ट प्रस्तुत की साथ ही माननीय दिल्ली हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ग्वालियर हाई कोर्ट, जम्मू और कश्मीर हाई कोर्ट, एवं अन्य हाईकोर्ट जो NEHM के पक्ष में आदेश दिये हैं, न्यायालय इलाहाबाद को 527 पेजों का, (जिसमें सन् 1983 से 2009 तक की क्रिया-विधि को अवगत कराया) Supplementary Affidavit प्रस्तुत किया, माननीय न्यायालय ने, भारत सरकार की समस्त दलीले सुनने के बाद, 3 अगस्त 2009 को ऐतिहासिक फैसला सुनाया, अपने फैसले में, सचिव स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार से कहा, कि पिटीशनर (NEHM) के पास Electropathy के पक्ष में कितने हाई कोर्ट के आदेश हैं, साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। माननीय उप-स्वास्थ्य मंत्री भारत सरकार ने 31.05.1991, को NEHM कार्यालय का निरीक्षण किया था, तत्पश्चात 14/17.06.1991 को NEHM को प्रचार, प्रसार व अनुसंधान हेतु अधिकृत (Authorised) किया, का भी आदेश है, अतः 6 माह के अंदर BEMS कोर्स को मान्यता हेतु कायवाही करें, यह आदेश देते हुए 18 साल पुरानी याचिका को Disposed of कर दिया। NEHM ने प्रार्थना-पत्र के साथ 527 पेजों का आवेदन सितम्बर 2009 में न्यायालय इलाहाबाद के आदेश पर, सचिव स्वास्थ्य मंत्रालय भारत सरकार के समक्ष Electropathy पद्धति को मान्यता हेतु प्रस्तुत किया।

उप-सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, निर्माण भवन, भारत सरकार का 5 मई 2010 की बनायी हुई Policy Decision/Notification के अनुसार अब तक इन 29 सालों में जो भी NEHM ने इलेक्ट्रोपैथी के पक्ष में किया, उसका उल्लेख किया गया है, साथ ही खुशी की बात है, 17.06.1991 आदेश अधिकृत (Authorised) को स्वीकार कर लिया। अतः NEHM को स्वास्थ्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा P.D.R. हेतु अधिकृत कर दिया गया, सरकार के 5 मई 2010 के आदेश में Promotion Development में Practice एवं शिक्षा को स्वीकार कर लिया गया। NEHM हमेशा से यही कहा है कि हमें भारत सरकार से इलेक्ट्रोपैथी की प्रचार, प्रसार व अनुसंधान हेतु अधिकार पत्र प्राप्त होने के बावजूद भी Practice और शिक्षा से, सरकार रोकती आ रही है।

5 मई 2010 के आदेश में सरकार ने कहा कि मैंने Practice एवं शिक्षा कभी नहीं रोका, एवं जैसे ही मेरे द्वारा इलेक्ट्रोपैथी पद्धति का कानून बनाया जाता है, आप सभी को **Would be Regulate** नियमित कर दिए जाएंगे।

आप सभी यह ज्ञात ही होगा, कि भारत सरकार ने पूर्व अर्थात् 1988 एवं 1991 में भी इलेक्ट्रोपैथी को मान्यता हेतु जो **Inquiry एवं Expert Committee** बनायी थी, उसमें NEHM को मात्र विशेषज्ञ के रूप में मनोनित किया। अतः NEHM of India ने 29 वर्षों के बाद वह स्थान प्राप्त कर लिया, जिसे हम सभी प्राप्त करना चाहते थे। 05.05.2010 के आदेश को देखे, तो अब मान्यता हेतु न तो कोई कमेटी बनेगी, और न ही चिकित्सक लोग अब अनशन करेंगे, बस अब सरकार को **Central Council of Electropathy** को बनाने के लिए Finance मंत्रालय से पैसों की व्यवस्था करनी है, और जैसे ही पैसा प्राप्त होता है, वैसे ही लोक सभा, राज्य सभा में बिल पास होने के बाद माननीय राष्ट्रपति को मोहर लगाने के बाद, इलेक्ट्रोपैथी का कानून बन जायेगा, एवं NEHM के समस्त चिकित्सक व मेडिकल कॉलेज, भारत सरकार के दायरे में आ जायेंगे।

मैं यहाँ स्पष्ट करना चाहता हूँ कि गुजरात हाई कोर्ट के Chief Justice एवं जस्टिस दवे ने भारत सरकार के सरकारी वकील से 5 मई 2010 के आदेश पर, जिसमें माननीय Chief Justice ने 30 अगस्त 2010 को लिखित आदेश में कहा कि **5 मई 2010 का आदेश एक Policy Decision** है, एवं कानून के तहत राज्य सरकार पर यह Bound होता है,

अतः 5 मई 2010 से पहले किसी भी न्यायालय में NEHM के संस्थान एवं चिकित्सक के विरुद्ध कोई आदेश है, तो वह समाप्त समझें जाएंगे, बस आपको 05.05.2010 का आदेश लगाना है। 27 वर्ष में केन्द्र सरकार ने पहली बार NEHM एवं इलेक्ट्रोपैथी के प्रति आदेश Practice एवं शिक्षा को बरकरार रखा, ये आदेश न होने के कारण तभी राज्य सरकार, हमें आप को परेशान करती रही हैं।

बड़ी खुशी की बात है, हर राज्य को माननीय उच्च न्यायालय, 5 मई 2010 के आदेश को देखते हुए राज्य सरकार को आदेश दे रही है, कि वों 5 मई 2010 के आदेश को Comply करें। जिसमें गुजरात सरकार ने राज्य में उक्त आदेश लागू कर दिया। अतः गुजरात राज्य में NEHM के चिकित्सक ही Practice करेंगे। उत्तर प्रदेश, राज्यस्थान एवं पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट, ने गुजरात हाई कोर्ट के तर्ज पर ये आदेश पारित कर दिए हैं, सबसे बड़ी उपलब्धि है कि हर राज्यों ने 5 मई 2010 के केन्द्र सरकार के आदेश को इज्जत दी। सभी राज्य सरकारें, केन्द्र सरकार के अधीन हैं एवं NEHM भी केन्द्र सरकार के अधीन अधिकृत है न की राज्य सरकार के।

भारत सरकार ने एक अन्य आदेश दिनांक 21.06.2011 के तहत समस्त राज्यों तथा केन्द्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य सचिवों को सूचित भी कर चुकी है, कि भारत सरकार द्वारा पारित 05.05.2010 का आदेश को एक Instructions के रूप में समझा जायें तथा क्रियान्वन (Implementation) में लाया जाये। कुछ राज्यों जैसे हरियाणा, यू0पी0, हिमाचल प्रदेश, मेघालय तथा नागालैंड ने उक्त आदेश को Implement भी कर दिया है, जिससे प्रान्त के NEHM से पंजीकृत इलेक्ट्रोपैथी चिकित्सक पूर्ण रूप से चिकित्सा व्यवसाय कर रहे हैं।

अभी हाल ही में अर्थात् 29.06.2012 को केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय भारत सरकार ने एक आदेश पारित किया कि पूर्व में मंत्रालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 05.05.2010 तथा 21.06.2011 के आधार पर स्वास्थ्य मंत्रालय, भारत सरकार ने इलेक्ट्रोपैथी/ इलेक्ट्रो होम्योपैथी को अपने अधीन (Governed) कर लिया है। इस आदेश का अभिप्राय यह है, कि सरकार ने इलेक्ट्रोपैथी को Interim recognition दे दी है। अब मात्र Recognition under legislation शेष रह गया है, इस महत्वपूर्ण आदेश का संपूर्ण श्रेय 05.05.2010 को पारित पॉलिसी डिस्मिशन को जाती है, क्योंकि मा0 सर्वोच्च न्यायालय ने पुष्टि भी कर चुकी है, कि सरकार द्वारा पारित पॉलिसी डिस्मिशन में कोर्ट कोई उलंघन (Interference) नहीं कर सकती। अतः 05.05.2010 का आदेश पूर्णरूप से NEHM of India के लिये ही प्रभावी है।

1983 से आज तक जितने भी हमने NEHM चिकित्सक बनाए हैं उनकी पूरी list हम शीघ्र केन्द्र सरकार को सौंप रहे हैं।

समस्त अखबारों में सही स्थिति को अबगत कराना मेरा मुख्य ध्येय यह है, कि हजारों की संख्या में अन्य बोर्ड/संस्था/ कौंसिल से बी0ई0एम0एस0, डी0ई0एच0एम0 करके इलेक्ट्रोपैथी में प्रेक्टिस कर रहे हैं, परंतु 05.05.2010, 21.06.2011, 29.06.2012 भारत सरकार के आदेश के तहत उनकी समस्त डिग्री, डिप्लोमा व प्रमाण पत्र की मान्यता/रदद/ भंग हो चुके हैं, अतः आपसे अनुरोध है, कि समस्त उपरोक्त आदेशों को देखकर आपको समय दिया जाता है, कि आप NEHM of India से डी0ई0एच0एम0, बी0ई0एम0एस0 करके एक योग्य इलेक्ट्रोपैथी चिकित्सक बनें, एवं 05.05.2010 पॉलिसी डिस्मिशन के आधार पर आपका भी नाम योग्य इलेक्ट्रोपैथी चिकित्सको की लिस्ट में जोडा जा सकें।

एन0ई0एच0एम0ऑफ0इंडिया  
अधिकृत: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार

**जनहित में जारी**

No.V.25011/130/2012-HR  
Government of India  
Ministry of Health & Family Welfare  
(Deptt. of Health Research)

By Speed Post

Nirman Bhawan, New Delhi  
Dated the 29<sup>th</sup> June 2012

To ✓  
Sh Ashok Kumar,  
(CMMEO Office)  
Amar Maya Enclave, Chandpur Road,  
Distt Bulendsahar, Uttar Pradesh-203001.

Sub: RTI application dated 06-06-2012 seeking information regarding Electropathy/  
Electrohomeopathy.

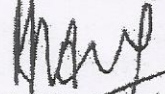
Sir,

I am to refer to your RTI application dated 06-06-2012 on the above subject  
and to furnish information as under:-

*The Electropathy/Electrohomeopathy is governed by the Ministry of Health  
and Family Welfare order No. C-30011/22/2010-HR dated 21-06-2011 along with  
enclosures (which included order No V-25011/276/2009/HR dated 5/5/2010) on the  
subject enclosed herewith is self explanatory. It is also informed that a Bill for  
'Recognition of New System of Medicine' is under consideration of the Government,  
and no further information is available in the matter.*

2. Sh S.K. Rao, Joint Secretary in the Department of Health Research is the appellate  
authority under Section 19(1) of the RTI ACT-2005. His office address is Room No 252, A Wing  
Nirman Bhawan, New Delhi-110011.

Yours faithfully



(R.K. Ahlawalia)

Under Secretary to the Govt. Of India

Copy to:

- 1.Cdn II Section with reference to their FTS No 45143/2012.
2. Hindi Section for Hindi version.

**ORDER**

This order is passed in pursuance of High Court of Allahabad order dated 3.8.2009 in Civil Miscellaneous Writ Petition No. 31904 of 1991, in which the Court has directed that, "the petitioner may file a fresh representation before the Ministry of Health & Family Welfare, New Delhi, bringing on record various orders passed by various High Courts and that of the Supreme Court. If such a representation is made with regard to recognition of the course, the authority will consider and decide that matter by a reasoned and speaking order within six months from the date of the production of a certified copy of this order with the representation. If necessary, the petitioner would be accorded personal opportunity of hearing by the respondents".

The NEHM through Dr N K Awasthy filed a representation dated 28.10.2009 before the Secretary, which was received on 31.11.2009. The major issues raised in this representation are as follows:

1. Electropathy is a medical system based on herbal and its medicines are prepared from medicinal plants with the help of distilled water. Its medicines are therefore 100% safe and curative.
2. Not a single complaint/ case has been reported/ registered with the Government regarding death of any patient.
3. There have been various Court judgments supporting electropathy. In support of this contention, the representation has annexed copies of orders relating to these cases.
4. Apart from the Court cases, the representation has also submitted affiliation with World Council, Reports of GB Pant University of Agriculture & Technology, letters from Deputy Minister of Health & Family Welfare dated 14.6.91 & 17.6.91, letter from Government Medical Councils, answers to Parliament questions, notification of directorate of health services, Government of NCT of Delhi, private member bill, letter from former Minister of Health & Family Welfare, article published in the Indian Journal of Veterinary Medicine, Punjab Agricultural Magazine, Ludhiana, Notification of J &K Government and letter of SSP Agra (UP), letter of Government of MP, as well as some publications (books & magazines ) on electropathy.
5. Dr Awasthy has represented that the Health Ministry should honour the judgment and give shelter to Electropathy Medical System by permitting NEHM for promotion, development & Research (Education & Practice) in Electropathy Medical System at least initially for 15 years so that the necessary criteria for the recognition of a new medical system may be achieved without any hindrances.



6. The representation was examined in the Ministry. The facts are as follows:

The following orders of the Court have been submitted:

- i) Order dated 14.8.92 within Suit No 27 of 1992 by Additional District Judge, Delhi has directed that No public notice be issued concerning the activity of the plaintiff during the pendency of the suit.
- ii) Order of High Court of Delhi dated November 1998, in FAO No. 1205 of 1998: In public notice it will not be stated that the persons possessing the diploma/ certificates from the respondent No 10 are not entitled to practice Electro Homeopathy system of Medicine.
- iii) Order of Hon'ble Supreme Court made on 12.01.2000 in SLP No 11262/2000 (Union of India vs Naturo Electro Homeo Medicose of India):

*"Learned counsel for the respondent has pointed out that as per his instructions the order made by the High Court in C.W.P No. 4015/96 to the extent indicated at page 4 of the paper book has been accepted by the petitioners and in view of the matter the impugned direction given by the High court is unexceptionable"*

*"In view of the order made by us on 12.10.2000 and that no proceedings having been initiated, challenging the order made in the C.W.P No.4015/96, we decline to entertain the matter."*

- iv) Order of High Court of Jabalpur, MP: 2957/94 dated 19.3.1999 which essentially stated that the degree/diploma obtained by them are not recognized under any law. The practice in alternative system of medicine is not regulated by any statute & hence in the absence of regulation/ prohibition they cannot be asked to stop practice. No legislation governing practice or teaching in alternate system of medicine has been enacted either by the Union or the State. In this case the MP Government has taken action under the MP Ayurvigyan Parished Adhinyam 1990. The Court held that this Act applies only to allopathic system of medicine and also stated that no other law was brought to the notice of the Court. So long as a valid law is not made regulating this branch, therefore stopping the petitioners from practicing in alternative system of medicine or imparting education is illegal.
- v) Order of High Court of Madhya Pradesh at Jabalpur bench, Gwalior in WP No 2462/08 in which directions were given that orders in WP 2957/94 shall apply.

.....3/-



Apart from the above, Letter D.O. No. 2921/ DM (H&FW)91/VIP dated 17.6.1991 from Dasai Chowdhry, Deputy Minister of Health & Family Welfare to Shri Jagannath Singh, MP has been annexed, which states that:

"I have authorized N E H M of INDIA for the Development Promotion & Research of electropathy in India"

The Government of India issued an Order No. R. 14015/25/96-U & H(R) (pt) dated 25<sup>th</sup> November 2003, based on the recommendations of a "Standing Committee of Experts" under the chairmanship of Director General ICMR, set up by the Government of India. Based on the recommendations of the Committee, the Government of India has given the following orders:

The committee did not recommend recognition to alternative medicines except Ayurveda, Siddha, Unani, Homeopathy & Yoga & Naturopathy which were found to fulfill the essential & desirable criteria developed by the Committee for recognition of a system of medicine.

The Committee further recommended that all systems of medicine not recognized as separate systems should not be allowed to continue full time Bachelor and Masters degrees and the term doctor should be used only by practitioners of systems of medicine recognized by Government of India. Those considered as mode of therapy can be conducted as certificate courses for registered medical practitioners.

The Committee, however, recommended that certain practices as Acupuncture which qualified as modes of therapy, could be allowed to be practised by registered practitioners or appropriately trained personnel.

The Committee, based on the essential & desirable criteria, did not find electropathy to qualify as a system of medicine. Therefore, it is clear that, in accordance with this order, electropathy cannot run full time Bachelor and Masters degrees and those practicing this cannot use the term "doctor".

NEHM, as per the document submitted by them is conducting diploma and certificate courses, and not running full time Bachelor and Masters degrees.

In so far as recognizing the courses run by them, it is clarified that the concerned boards/statutory bodies like the Medical Council, give recognition to courses. Since electropathy is not recognized as a system of medicine, there is no system for recognition of any course run by them in the Health Ministry.

NEHM, has also not submitted any document according to which they fulfill the essential & desirable criteria developed by the Committee for recognition of a system of medicine.

However, the Order No. R. 14015/25/96-U & H(R) (pt) dated 25<sup>th</sup> November 2003, does not bar the Development & Research of Electropathy.



In accordance with Orders of the High Court & Supreme Court quoted here, there is no proposal to stop the petitioners from practicing in electropathy or imparting education, as long as this is done within the provision of the Order No. R. 14015/25/96-U & H (R) (Pt) dated 25<sup>th</sup> November 2003. Once the legislation to recognize new systems of medicine is enacted, any practice or education would be regulated in accordance with the said Act. The representation of the petitioner dated 28.10.2009 is disposed off accordingly.

This issues with the approval of Secretary, Department of Health Research in this Ministry.



(MOHD. SALEEM)

Under Secretary to the Government of India of India

Tel No.23061986

To

N. E. H. M. of India, H.O. C-2 C/123, Pocket 12, Janak Puri, New Delhi - 110058.

Copy for information and necessary action to :

1. Shri Ravi Bhushan Singhal, Assistant Solicitor General of India, , 200 , Lukerganj, Allahabad. (U.P)
2. Shri Ravi Bhushan Singhal, Assistant Solicitor General of India, High Court of Allahabad, Allahabad. (U.P):



(MOHD. SALEEM)

Under Secretary to the Government of India of India

No.C.30011/22/2010-HR  
Government of India  
Ministry of Health & Family Welfare  
(Department of Health Research)  
\*\*\*\*\*

Nirman Bhawan, New Delhi;  
Dated: 21.06.2011.

ORDER

Subject:- Regarding practice, education and research in alternative system of medicine

An order was passed on 11.10.2010 by the Lucknow Bench of the Hon. High Court of Judicature at Allahabad in the WP No.3992/2004 filed before the Hon. High Court of Judicature at Allahabad at Lucknow Bench. In Electro Homeo Medical Association of India vs. State of UP & 4 Ors. as under:

*Heard Learned counsel for the parties and perused the record.*

*With regard to its grievance, the petitioner may make a representation within a month from today in the light of the Government Order dated 5.5.2010 (No.V.25011/276/2009-HR) issued by the Government of India, Ministry of Health & Family Welfare Department of Health Research.*

*If the representation made by the petitioner within the aforesaid period, the same shall be decided by the Government of India within three months from the date of its filing.*

*With above observation, the writ petition is finally disposed of.*

2. Consequently, in accordance with the said order, Sh. Taj Ali, Secretary, Electro Homeo Medical Association of India, Lucknow has filed a representation in the matter vide his letter dated 03.11.2010 in which he has made the following submissions and prayer:-

*That the order dated 25.11.2003 addressed to different officials and copies sent, however, to all their subordinates was mis-interpreted as if the Government of India has altogether prohibited the development and research of Electropathy, however the order dated 05.05.2010 has clarified that there is no proposal to stop the petitioner from practicing in electropathy or imparting education as long as this is done within the parameters of the order dated 25.11.2003 and once the legislation to recognize new system of medicine is enacted any practice or education would be regulated in accordance with the said Act.*

*On the basis of the order dated 25.11.2003 different authorities issued preventive orders as if there can be no teaching or practice in Electropathy/Electro Homoeopathy at all and that forced the applicant to file the above noted writ petition in the Hon'ble High Court Allahabad, Lucknow Bench, Lucknow. However in the meantime the order dated 05.05.2010 has clarified the position and the Hon'ble Division Bench in the light thereof has opined that now no detailed order is required to be passed and the petitioner may make the representation to the Government of India and Government of India may pass the order in the light of the order dated 05.05.2010.*

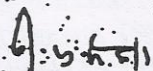
*It is, therefore, respectfully prayed, that the authorities to whom the order No.R.14015/25/96-U&H(R)(Pt.) dated 25.11.2003 was issued, may kindly be communi-*

cated to read the order in the light of the Government of India later order dated 05.05.2010 and act only in accordance with the same and may not cause any interference in contravention of the same."

As per the directions of the Hon. Lucknow Bench of the High Court of Judicature at Allahabad, the representation has been considered. It is clarified that the MH&FW Order No.R.14015/25/96-U&H(R)(Pt.) dated 25.11.2003 and No.V.25011/276/2009-HR dated 05.05.2010 would be treated as instructions of the Government of India related to practice, education and research with regard to alternative systems of medicine like electropathy, electro-homoeopathy, etc.

4. A copy of each of the said two orders viz. MH&FW Order No.R:14015/25/96-U&H(R)(Pt.) dated 25.11.2003 and No. V.25011/276/2009-HR dated 05.05.2010 is being forwarded herewith to each of the State Governments/UTs for information and necessary action. With this your representation is disposed off.

5. This issues with the approval of Secretary (Department of Health Research), Ministry of Health & Family Welfare, New Delhi.



(J. P. Mehta)  
Director (HR)

To,

All Health Secretaries of State Governments/Union Territory Administrations.

Copy to:

1. Sh. Taj Ali, Secretary, Electro Homeo Medical Association of India, 8 - Lal Bagh, Lucknow - 226001 (Uttar Pradesh).
2. The Registrar, High Court, Lucknow Bench, Lucknow.